INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL
ISSN NO : 2230-7850
IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF)
VOLUME - 16 | ISSUE - 2 | MARCH – 2026

"हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को आतंकवाद तथा क्षेत्रीय सुरक्षा"

विजय बहादुर साकेत
शोधार्थी राजनीति विज्ञान, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डॉ. गायत्री मिश्रा
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश –

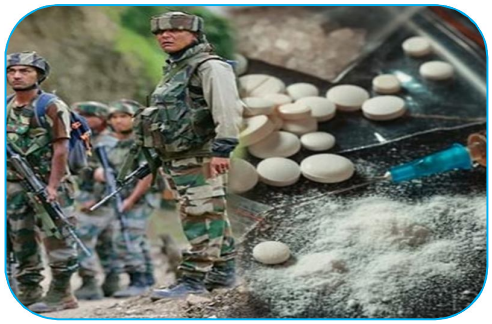

हिमालय क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति का केंद्र रहा है। शीतयुद्धोत्तर काल में जब आतंकवाद ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण किया, तब यह क्षेत्र भी आतंकवादी गतिविधियों से अछूता नहीं रहा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद चीन के साथ सीमा विवाद और स्थानीय विद्रोही आंदोलनों ने इस क्षेत्र को निरंतर अस्थिर बनाए रखा है। इसी के साथ नार्को–आतंकवाद अर्थात् नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवाद के लिए करना, यहाँ की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बन चुका है। हिमालय क्षेत्र की दुर्गम सीमाएँ, गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट से जुड़ाव तथा स्थानीय सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ नशा–तस्करी और आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं। इसके परिणामस्वरूप न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा संकटग्रस्त होती है, बल्कि समाज में हिंसा, नशाखोरी और सांस्कृतिक विघटन भी है। भारत ने सीमा प्रबंधन, आतंकवाद, विरोधी कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस समस्या से निपटने का प्रयास किया है, किंतु चुनौतियाँ अभी भी बरकरार हैं। यह अध्ययन हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की प्रकृति, कारणों और प्रभावों का अकादमिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है तथा स्थायी समाधान केवल सैन्य रणनीतियों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए क्षेत्रीय सहयोग, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की समन्वित नीतियाँ आवश्यक हैं।

मुख्य शब्द– *हिमालय क्षेत्र, आतंकवाद, नार्को–आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन आदि।*

प्रस्तावना –

हिमालय क्षेत्र प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के लिए सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। यह क्षेत्र न केवल भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, बल्कि एशिया की सामरिक राजनीति में भी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ उत्तर भारत को मध्य एशिया और चीन से अलग करती हैं तथा दक्षिण एशिया के देशों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं। किंतु आधुनिक समय में जब वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद जैसी समस्याएँ तीव्र रूप से उभरीं, तब यह क्षेत्र गहन संकटों का केंद्र बन गया। आज हिमालय केवल प्राकृतिक सुरक्षा कवच ही नहीं, बल्कि अनेक प्रकार की सामरिक और सुरक्षा संबंधी चुनौतियों का प्रतीक भी बन गया है।

हिमालय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियाँ आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। ऊँचे–ऊँचे पर्वत, दुर्गम दर्रे, घने वन और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जटिल संरचना आतंकवादी गतिविधियों

और नशा–तस्करी के लिए अवसर प्रदान करती है। भारत, चीन, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान जैसे देशों की सीमाएँ इस क्षेत्र से जुड़ी होने के कारण यहाँ की स्थिति और अधिक जटिल हो जाती है। विशेषकर भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर मुद्दा तथा भारत और चीन के बीच सीमाविवाद ने इस क्षेत्र को निरंतर अस्थिर बनाए रखा है।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आतंकवाद का वैश्विक स्वरूप बदला और यह समस्या केवल पश्चिम एशिया या अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने जम्मू–कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को गहराई से प्रभावित किया है। साथ ही अफगानिस्तान में पनपने वाला चरमपंथ भी इस क्षेत्र की अस्थिरता का कारण बना। दूसरी ओर, उत्तर–पूर्व भारत से सटे हिमालयी क्षेत्र म्यांमार और गोल्डन ट्रायंगल से जुड़े होने के कारण नशा–तस्करी का प्रमुख मार्ग बन गए। इस प्रकार हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद ने मिलकर एक गहरे संकट का रूप ले लिया।

नार्को–आतंकवाद का स्वरूप विशेष रूप से चिंताजनक है। इसमें नशीले पदार्थों के अवैध उत्पादन और व्यापार से प्राप्त धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए किया जाता है। गोल्डन क्रेसेंट (ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान) और गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, लाओस, थाईलैंड) जैसे क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। हिमालय क्षेत्र इन दोनों से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ता है, जिसके कारण यह नशीले पदार्थों की तस्करी का मार्ग बन गया है। नशा–तस्करी और आतंकवाद का यह गठजोड़ क्षेत्रीय सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय विकास के लिए गंभीर खतरा बन चुका है।

इस समस्या ने हिमालय क्षेत्र की क्षेत्रीय सुरक्षा को बहुआयामी रूप से प्रभावित किया है। राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए चुनौती है। सीमा पार से आतंकवादी घुसपैठ, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी ने भारत और पड़ोसी देशों को सतत् सतर्क रहने के लिए विवश किया है। सामाजिक संरचना को तोड़ता है, जैसे नशे के जाल में फँसकर युवा पीढ़ी न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती है, बल्कि आतंकवादी संगठनों के लिए आसानी से उपलब्ध मानव संसाधन भी बन जाती है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बाधित करता है। जब किसी क्षेत्र का वातावरण असुरक्षित होता है, तो निवेश और विकास कार्य ठप्प पड़ जाते हैं।

भारत ने इस संकट से निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सीमा सड़क संगठन, भारत–तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स जैसी संस्थाएँ सीमाओं को सुरक्षित करने का कार्य की हैं। आतंकवाद निरोधक अधिनियम और नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट जैसे कानून बनाये गये हैं। साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर SAARC, BIMSTEC और संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई की वकालत की है। किंतु इन प्रयासों के बावजूद समस्या का समाधान पूरी तरह संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की जड़ें सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय कारकों से जुड़ी हुई हैं।

हिमालय क्षेत्र की सुरक्षा की समस्या केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं सुलझाई जा सकती। इसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। एक ओर सुरक्षा बलों को सीमा प्रबंधन और आतंकी गतिविधियों से निपटना होगा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता देनी होगी। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर स्थानीय युवाओं को नशे और आतंकवाद से दूर रखना होगा। इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ सहयोग और संवाद को बढ़ाना भी अनिवार्य है।

इस शोध–पत्र की प्रस्तावना से यह स्पष्ट है कि हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की समस्या केवल भारत की नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की है। यह न केवल सुरक्षा का प्रश्न है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट का भी संकेतक है। अतः इस अध्ययन का उद्देश्य इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना और यह देखना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों की आवश्यकता है।

शोध का उद्देश्य –

शोध पत्र प्रारंभ करने से पूर्व यह निश्चिय करना परम आवश्यक होता है कि शोध से संबंधित सूचनाओं का गहन अध्ययन करना नवीन प्रश्नों का निर्माण, अवधारणाओं एवं समझ को विकसित करने हेतु तत्वों का पता

लगाना तथा नवीन सम्भावनाओं को खोजना शोध कार्य का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। शोध की अवधारणा प्रत्येक क्षेत्र में होती है, जिससे प्रत्येक क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाया जा सके। अध्ययन का क्षेत्र तो बहुत व्यापक है, परन्तु व्यापक क्षेत्र में ही शोध के निश्चित उद्देश्यों से संबंधित तथ्य ही एकत्र किये जायेंगे। प्रस्तावित शोध पत्र से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्माण किया गया है, जो इस प्रकार है–

- हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करना।
- आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद के कारण राष्ट्रीय सीमाओं, सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन अध्ययन करना।
- समाधान और नीति–निर्माण हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

विश्लेषण –

हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की समस्या बहुआयामी स्वरूप लिए हुए है। सोद्देश्य के अंतर्गत यदि हम इसकी प्रकृति और स्वरूप का अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यहाँ आतंकवाद केवल राजनीतिक असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क और पड़ोसी देशों की नीतियों से गहराई से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, अफगानिस्तान में पनपे चरमपंथ और चीन के सामरिक हितों ने इस क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखा है। नार्को–आतंकवाद ने इस समस्या को और जटिल कर दिया है क्योंकि नशा–तस्करी से प्राप्त धन आतंकवादी संगठनों को पोषण देता है और स्थानीय युवाओं को हिंसा व अपराध की ओर मोड़ता है।

क्षेत्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन किया जाए तो स्पष्ट है कि आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद ने न केवल सीमा प्रबंधन को चुनौती दी है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को भी कमजोर किया है। लगातार होने वाली आतंकी गतिविधियाँ और नशा–तस्करी ने स्थानीय समाज में भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण पैदा किया है। आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र विकास की गति से पिछड़ता जा रहा है क्योंकि संसाधनों का बड़ा हिस्सा सुरक्षा उपायों पर खर्च होता है। राजनीतिक स्तर पर भी अस्थिरता बढ़ी है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की मजबूती पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।

यह अध्ययन इंगित करता है कि केवल सैन्य उपायों से समस्या का समाधान संभव नहीं है। भारत ने सीमा प्रबंधन, आतंकवाद निरोधक कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं, किंतु स्थायी समाधान के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। सामाजिक स्तर पर युवाओं को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास की दिशा में प्रेरित करना होगा ताकि वे नशे और आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहें। आर्थिक दृष्टि से क्षेत्रीय विकास, आधारभूत संरचना और व्यापार को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। साथ ही सामरिक दृष्टि से पड़ोसी देशों के साथ संवाद और सहयोग की नीतियाँ मजबूत करनी होंगी।

इस प्रकार विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से निष्कर्ष निकलता है कि हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की चुनौती केवल सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता से जुड़ा हुआ व्यापक संकट है। इसका समाधान तभी संभव है जब बहुस्तरीय और समन्वित नीतियाँ अपनाई जाएँ जिनमें सुरक्षा, विकास और सहयोग तीनों को समान महत्व मिले।

निष्कर्ष –

हिमालय क्षेत्र अपनी भौगोलिक, सामरिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के कारण सदैव एशिया की राजनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता रहा है। किंतु पिछले कुछ दशकों में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की बढ़ती गतिविधियों ने इसे गहरे संकट में डाल दिया है। पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद, अफगानिस्तान से जुड़ा चरमपंथ, चीन के साथ सीमा विवाद और उत्तर–पूर्व भारत में सक्रिय उग्रवादी संगठन इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे के रूप में उभरे हैं। इसके साथ ही नशा–तस्करी ने स्थानीय समाज को प्रभावित किया है और युवाओं को हिंसा व अपराध की ओर धकेला है। क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से यह स्पष्ट है कि आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद केवल सैन्य चुनौती नहीं हैं, बल्कि इनका संबंध

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों से भी है। नशा–तस्करी से प्राप्त धन ने आतंकवादी संगठनों को आर्थिक आधार प्रदान किया है, जबकि इसके दुष्प्रभावों ने समाज की संरचना को कमजोर किया है। परिणामस्वरूप स्थानीय असंतोष और अलगाववाद की प्रवृत्तियाँ और अधिक गहरी होती गई हैं। भारत ने सीमा प्रबंधन, आतंकवाद–निरोधी कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से अनेक प्रयास किए हैं, किंतु स्थायी समाधान तभी संभव है जब विकास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय को समानांतर रूप से प्राथमिकता दी जाए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान के बीच आपसी सहयोग और विश्वास को मजबूत करना भी आवश्यक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिमालय क्षेत्र में आतंकवाद और नार्को–आतंकवाद की चुनौती बहुआयामी है और इसका समाधान भी बहुआयामी होना चाहिए। यदि सैन्य रणनीतियों के साथ सामाजिक–आर्थिक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को जोड़ा जाए तो यह क्षेत्र न केवल सुरक्षित बन सकता है, बल्कि एशिया में शांति और स्थिरता का आदर्श भी प्रस्तुत कर सकता है।

संदर्भ –

1. सिंह, महेंद्र प्रताप, भारतीय उपमहाद्वीप में आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियाँ, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 2018
2. शर्मा, आर.के., नार्को–आतंकवाद और दक्षिण एशिया की सुरक्षा, प्रकाशन संस्थान, भोपाल, वर्ष 2017
3. बोस, सुमंत्र, कश्मीर : संघर्ष की जड़ें और शांति के मार्ग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज, वर्ष 2005
4. रिजवी, हसन–अस्करी, पाकिस्तान और भू–राजनीतिक परिवेश, पॉलग्रेव मैकमिलन, लंदन, वर्ष 2000
5. थापा, दीपक, नेपाल में माओवादी आंदोलन की समझ, मार्टिन चौतारी प्रेस, काठमांडू, वर्ष 2003
6. संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (यूएनओडीसी), विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, वियना, वर्ष 2022